Hindustan, 25 Sep 2008

मिडफो बदलेगा मेरठ की औद्योगिक सूरत

कार्यालय संवाददाता मेरठ

औद्योगिक बदहाली से जूझ रहे मेरठ की सूरत बदलने का बीड़ा अब मिडफो ने उठाया है। बुधवार को मिडफो ने प्रख्यात आर्किटेक्ट और अरबन प्लानिंग एक्सपर्ट आरजी गुप्ता को बुला कर उनके साथ उद्यमियों की बैठक कराई। बैठक में यहां के औद्योगिक जगत के वर्तमान हालात, उपलब्ध संसाधनों तथा भविष्य की जरूरतों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सदस्यों ने मास्टर प्लान में औद्योगिक आस्थानों की स्थिति, टेक्नालाजी पार्कों की स्थापना तथा सेज की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे और कहा कि अब बिना सरकारी मदद के ही आगे बढ़ना होगा।

मेरठ इंडस्ट्रियल फोरम के बैनर तले बुधवार को उद्यमियों ने वेस्टर्न यूपी चैंबर आफ कामर्स में अरबन प्लानर और एमडीए के कंसलटेंट आरजी गुप्ता के साथ बैठक भविष्य

बांबे बाजार स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में मेरठ औद्योगिक विकास फोरम की बैठक को टाउन प्लानर आरजी गुप्ता ने सम्बोधित किया।

के मेरठ का खाका खींचा। मिडफो के अध्यक्ष हेमंत कुमार ने उद्यमियों की ओर से यहां की औद्योगिक जरूरतों को उठाते हुए कहा कि महायोजना 2021 में कम से कम 2500 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाना जरूरी है। इसके अलावा दिल्ली के लिए 6 लेन का हाइवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सीपीटी, दोहरी रेलवे लाइन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं का विकास, बिजली की निर्बाध उपलब्धता और सस्ते और स्वच्छ ईंधन विकल्प के रूप में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति जैसी मांगों को भी दोहराया गया। मिडफो की भूमिका के बारे में बताते हुए हेमंत कुमार ने कहा कि हमारे प्रयासों से मेरठ में 8 औद्योगिक कलस्टरों को स्वीकृत किया जा चुका है। आज की गोष्ठी का मकसद अगले कदम के लिए विस्तृत रणनीति पर विचार करना था। ताकि सरकार से सुविधाओं की मांग करते समय अपनी जरूरतों को सही तरीके से सामने रख सकें। उधर आरजी गुप्ता ने उद्यमियों से अपील की कि वे सरकार पर निर्भरता को कम रखते हुए यहां के औद्योगिक विकास के लिए आगे आएं और निजी क्षेत्र के निवेशकों के सहारे अर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करें। बैठक के बाद वेस्टर्न यूपी चैंबर आफ कामर्स के सचिव ने बताया कि आज की बैठक में आए प्रस्तावों के आधार पर सरकार को जल्द ही एक मेमोरंडम भी सौंपा जाएगा।

Amar Ujala, 25 Sep 2008

औद्योगिक विकास को सहयोग दे सरकार

- मेरठ औद्योगिक विकास फोरम की बैठक में उपेक्षा पर रोष जताया
- दिल्ली की तर्ज पर हो मेरठ का नियोजन : आरजी गुप्ता

मेरठ : अरबन प्लानिंग विशेषज्ञ आरजी गुप्ता ने स्वीकार किया कि औद्योगिक विकास का माहौल तैयार करने के लिए सरकार को प्राथमिकता के आधार पर सहयोग करना चाहिये। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर मेरठ का नियोजन होने की पैरोकारी की परन्तु उद्यमियों ने शासन व प्रशासन स्तर पर सहयोग न मिलने का दर्द बयां किया।

मेरठ औद्योगिक विकास फोरम की पहल पर बुधवार को बांबे बाजार स्थित वेस्टर्न चैम्बर आफ कामर्स के मोदी सभागार में अपराह्न साढ़े तीन बजे महानगर के प्रमुख उद्यमी क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर चर्चा करने को जमा हुए। उद्योगों की स्थापना के मास्टर प्लान में औद्योगिक पार्क, सेज आदि मसलों पर सुझाव देने के लिए दिल्ली के नियोजन में विशेष भूमिका निभाने वाले आरजी गुप्ता भी मौजूद थे। श्री गुप्ता ने दिल्ली के नजदीक होने व एनसीआर में प्रमुख महानगर होने पर औद्योगिक विकास में मेरठ की महत्ता को स्वीकारा। मेरठ में औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने महायोजना-2021 में आवश्यक

चैंबर आफ कामर्स बोम्बे बाजार में मेरठ औद्योगिक विकास फोरम के कार्यक्रम को सम्बोधित करते मुख्य अतिथि आरजी गुप्ता। जागरण

सुधारों पर भी जोर दिया। इसके लिए आरक्षित एरिया बढ़ाने की पैरोकारी की। उन्होंने इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने की बात भी कहीं। उनका कहना था कि किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए भविष्य की जरूरतों को भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग, तकनीकि, पर्यावरण, जलापूर्ति, पावर, सुरक्षा, परिवहन, संचार साधन व मनोरंजन आदि की व्यवस्था होने की बात कही। उनका कहना था कि पब्लिक-प्राईवेट सेक्टर को मिलकर विकास की संभावनाएं तलाशनी होगी। इसके लिए केन्द्र व प्रदेश सरकारों को अपनी हिस्सेदारी सत्तर प्रतिशत सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने मेरठ का दिल्ली की तर्ज पर नियोजन किये जाने पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को पहल करनी होगी। बाहर की पूंजी आने के लिए भी उपयुक्त माहौल तैयार करना होगा। जिसमें अब्दुल्लापुर इंडस्ट्रीयल एरिया न विकसित हो पाने से लेकर बिजली संकट, सड़कों की जर्जर हाल, सिंगल विंडो सिस्टम न होना और कानून व्यवस्था आदि समस्याओं को गिनाया। इस मौके पर हेमंत कुमार, सुरेन्द्र प्रताप, आरके जैन, राजकुमार कौशल, कपिल अग्रवाल, अशोक जैन, पंकज, जगेश कुमार व अतुल आदि उपस्थित रहे।

बारिश पर जारी ब्लेम गेम में पानी-पानी होती दिल्ली

थोड़ी सी बारिश और दिल्ली दरिया में बदल जाती है। सड़क पर दिखाई देता है पानी और घंटों तक लगने वाला लंबा जाम। हर बारिश लोगों के पसीने छुड़ा देती हैं। इसका कारण पूछो, तो सभी सिविक एजेंसियां एक दूसरे के दामन पर कीचड़ उछालना शुरू कर देती हैं। तो आखिर इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है? प्रशांत सोनी बता रहे हैं कि दिल्ली में अलग-अलग कामों में लगी सभी सिविक एजेंसियों के पास अपने क्या तर्क हैं और एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है।

हम तो बस सिग्नल ही ठीक कर सकते हैं : ट्रैफिक पुलिस

ट्रैफिक तभी चलेगा, जब रोड क्लियर होगी। अगर रोड पर पानी भरा है या पेड़ टूटकर गिरा है, तो ट्रैफिक नहीं चल सकता। बारिश होने पर हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि अगर कहीं सिग्नल खराब हो गया है, तो वहां ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात कर दें। किसी रास्ते पर भारी जाम लगा है, तो वहां से ट्रैफिक दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट कर दें और जलभराव की सूचना संबंधित एजेंसियों को दे दें। यह हम करते हैं, लेकिन अन्य एजेंसियों की भी अपनी सीमाएं हैं। इससे सड़कों पर भरा पानी निकलने में वक्त लग जाता है। दरअसल जब तक ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। -**सत्येंद्र गर्ग**, जॉइंट कमिश्नर (ट्रैफिक)

हमारी ही गलती नहीं, और एजेंसियां सुधरें : एमसीडी

केवल एमसीडी जिम्मेदार नहीं है। किसी दूसरी एजेंसी के काम में कमी का खामियाजा पहली एजेंसी को भुगतना पड़ता है। अगर सिग्नल खराब है और वहां ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं है, तो एमसीडी को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर नाला साफ है, लेकिन सीवर लाइन साफ नहीं है, तो इसमें एमसीडी की क्या गलती है। वैसे इस साल गेम्स के कामों की वजह से ज्यादा दिक्कत हुई है। हमने पूरे साल नालों की सफाई का काम करवाया है। अगर बहुत तेज बारिश होती है, तो जलभराव हो ही जाता है। अन्य शहरों में भी ऐसा होता है। समस्या से निपटने के लिए एजेंसियों में हाई लेवल पर तालमेल जरूरी है। -**दीप माथुर, प्रवक्ता, एमसीडी**

पानी भरा तो पीडब्ल्यूडी की गलती : एनडीएमसी

जाम जलभराव की वजह से उतना नहीं लगता, जितना ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाने से लगता है। एनडीएमसी के इलाकों में जलभराव की ज्यादा समस्या नहीं है। हमारे एरिया में जिन जगहों में जलभराव होता था, उनमें से कई जगहों पर हमने पानी की निकासी के लिए पंप लगवा दिए हैं। हम अन्य एजेंसियों के साथ भी तालमेल बनाकर चल रहे हैं। पिछले दिनों अकबर रोड पर हुए जलभराव की वजह एनडीएमसी नहीं, बल्कि वहां चल रहा पीडब्ल्यूडी का काम था। शिकायत मिलते ही हमने तुरंत एक्शन लिया और पानी निकलवाया। आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे इलाके में जलभराव ना हो। -**आनंद तिवारी, प्रवक्ता, एनडीएमसी**

Rajesh Mehta

कोई भी एजेंसी ईमानदारी से काम नहीं करना चाहती : एक्सपर्ट

दिल्ली का ड्रेनेज प्लान उतना खराब नहीं है, जितना सबको लगता है, लेकिन ठीक से रखरखाव और साफ सफाई न किए जाने की वजह से नाले अब सीवर में तब्दील होती जा रहे हैं। नालों में इतनी गंदगी जमा है और उनमें से इतनी बदबू आती है कि उनके पास से गुजरना तक मुश्किल होता है। अगर हम सभी अपने आसपास के इलाके को साफ रखें और सिविक एजेंसियां सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तो यह समस्या हल हो सकती है। दिल्ली में कई सिविक एजेंसियां हैं। यहां कोई ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता। समस्याओं का ठीकरा सब एक दूसरे के सिर फोड़ते हैं। यह सही है कि पिछले कुछ सालों में दिल्ली में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है और यह आने वाले सालों में और बढ़ेगा, लेकिन सरकार अंडरग्राउंड सड़कें बनाकर और ऑल्टरनेट रास्ते बनाकर इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकती है। जाम की वजह से लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। -**आर.जी. गुप्ता, सिटी प्लानर और डीडीए के पूर्व अडिशनल कमिश्नर (प्लानिंग)**

हम तो सीवर ठीक करते हैं, ड्रेनेज नहीं : जल बोर्ड

हम केवल सीवर सिस्टम ठीक करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसे में अगर जलभराव होता है, तो हमें कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कई बार हम खुद परेशानी झेलते हैं। ज्यादा जलभराव हो जाता है, तो ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है। इसके बाद पानी सीवर लाइन में छोड़ दिया जाता है, जिससे वो भी ठप हो जाती है। कई बार ट्रैफिक भी रेगुलेट नहीं किया जाता, जिससे जाम लगता है। दिल्ली में बढ़ती की वजह से नाले और सीवर बनाने की जगह ही कहां है। मौजूदा नालों की कपैसिटी इतनी नहीं कि वे बारिश झेल सकें। कई बार नाले साफ नहीं होते, जिसकी वजह से समस्या और गंभीर हो जाती है। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें 3-4 घंटे की फ्लडिंग अलाउड है। -**रमेश नेगी, सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड**

हमारी तो किसी सड़क पर नहीं भरा पानी : पीडब्ल्यूडी

पीडब्ल्यूडी के हिस्से में आने वाली रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, महरौली बदरपुर रोड जैसी सड़कों पर न तो गड्ढे हुए हैं और ना कहीं बहुत ज्यादा जलभराव हुआ। दरअसल दिल्ली में ड्रेन की कपैसिटी लिमिटेड हैं और उनकी साफ सफाई और रखरखाव ठीक से नहीं होता है। इसी वजह से सड़कों पर पानी भर जाता है। अगर नालों की सफाई ठीक से हो, तो बारिश का पानी जल्दी से निकल सकता है। वैसे हमारे एरिया में जिन जगहों पर पहले जलभराव होता था, वहां हमने पानी निकालने के लिए पंप लगवा दिए हैं। शुरू में धौला कुआं पर दिक्कत हुई थी, लेकिन अब वहां प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेज बारिश के बाद जलभराव होता है, तो वह घंटे भर में निकल जाता है। यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। -**राकेश मिश्रा, इंजीनियर इन चीफ, पीडब्ल्यूडी**

हमारा एरिया है ही कितना बड़ा : डीडीए

पहली बात तो यह कि दिल्ली में हमारा एरिया बहुत थोड़ा ही है और जितना है वहां अब तक जलभराव की कोई ज्यादा समस्या नहीं हुई है। दरअसल डीडीए का काम तो कॉलोनियां बनाकर उन्हें उस इलाके की संबंधित सिविक एजेंसी को सौंप देते हैं। इसके बाद अगर उस इलाके में जलभराव होता है या जाम लग जाता है, तो उसे देखना उस संबंधित एजेंसी का काम है न कि हमारा। -**नीमो धर, प्रवक्ता, डीडीए**